संपादकीय जागरण

गुरुवार, 1 मार्च, 2018 : फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी/पूर्णिमा वि. 2074

असफलता निराशा का सूत्र नहीं बल्कि प्रेरणा का मंत्र है

प्रतीक्षित गिरफ्तारी

कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी प्रतीक्षित ही थी, क्योंकि वह जांच एजेंसियों के साथ लुकाछिपी का खेल खेलने में लगे हुए थे। इसके चलते ऐसे सवाल उभर रहे थे कि क्या सीबीआइ उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? कायदे से तो उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वह जांच में सहयोग करने के बजाय बहाने बनाने और अदालतों की दौड़ लगाने में लगे हुए थे? यह ठीक नहीं कि घपले-घोटाले के आरोपी के साथ इसलिए नरमी बरती जाए कि वह किसी राजनीतिक शख्सियत का परिजन है। सच तो यह है कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कहीं अधिक सख्ती दिखाई जानी चाहिए। इस पर हैरत नहीं कि खुद को तंग करने का रोना रो रहे पी चिदंबरम के बेटे की गिरफ्तारी होते ही कांग्रेस ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम कर रही है। यह वह बेसुरा राग है जो घपले-घोटाले में फंसा हर नेता अलापता है। कांग्रेसी नेता कार्ति की गिरफ्तारी पर ऐसे रुदन कर रहे हैं जैसे कांग्रेसी नेताओं अथवा उनके परिजनों को घपलेबाजी में लिप्त होने के आरोपों के बाद भी गिरफ्तारी से बचे रहने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आखिर ऐसे तर्कों का क्या मतलब कि कार्ति की गिरफ्तारी का वक्त ठीक नहीं। क्या इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाना चाहिए था? यह न केवल अजीब है, बल्कि हास्यास्पद भी कि सरकार को भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दे रही कांग्रेस भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में कार्ति की गिरफ्तारी के बाद आपा खो रही है। बेहतर हो कि वह यह समझे कि ऐसे घिसे-पिटे बयानों से बात नहीं बनने वाली कि विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है।

कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी आइएनएक्स कंपनी को कानूनी सीमा से अधिक विदेशी निवेश की जांच रुकवाने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में की गई है। सीबीआइ की मानें तो आइएनएक्स को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड यानी एफआइपीबी ने 4.62 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी अनुचित तरीके से तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक का निवेश ले लाई। जब इसका भंडाफोड़ हुआ और जांच की नौबत आई तो इस कंपनी की ओर से पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने कार्ति से संपर्क साधा। कुछ समय बाद तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने जांच बंद कर दी। बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी का कहना है कि जांच बंद कराने के लिए कार्ति को रिश्वत दी गई थी। अगर यह सब सच है तो फिर पी चिदंबरम भी जांच के दायरे में आएंगे। पता नहीं उनसे पूछताछ कब होती है, लेकिन सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ति के खिलाफ उनके पास जो भी प्रमाण हैं वे अदालत के समक्ष ठहर सकें। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रसूखदार लोगों के खिलाफ जांच के मामले में इन दोनों एजेंसियों का रिकॉर्ड बहुत दयनीय है और लोग अभी यह भूले नहीं हैं कि 2जी घोटाले का क्या हश्र हुआ?

होली पर बिजली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन को निर्देश दिया है कि होली पर बिजली की मांग का आकलन किया जाए और उसी के अनुरूप बिजली की आपूर्ति की जाए। इस निर्देश के आलोक में प्रमुख सचिव ने वितरण में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों से सतत सजगता बनाए रखने को कहा है। यह निर्देश भी दिया गया है कि होलिका दहन से बिजली लाइनों को कोई नुकसान न पहुंचे। बिजली विभाग त्योहार के मद्देनजर आवश्यक गैंग और आपात सामग्री की भी व्यवस्था करने में जुट गया है। वर्तमान में यदि कोई लोकल फाल्ट न हो तो, गांवों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालय वाले कस्बों और बुंदेलखंड को 20 घंटे और जिला मुख्यालय वाले कस्बों, उद्योगों और महानगरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कहा जा सकता है कि इस बार बिजली की कमी नहीं होगी और त्योहार में रंग के साथ रोशनी भी बनी रहेगी।

कहा जा सकता है कि इस बार होली के त्योहार में बिजली की कमी नहीं होगी और त्योहार में रंग के साथ रोशनी भी बनी रहेगी

कई प्रदेश अपनी सरप्लस बिजली नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं, इसी बिजली को नीलामी में बेस प्राइस पर खरीदने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। इस वक्त 30 से 35 प्रतिशत तक लाइन लास हो रहा है, इसमें बिजली की चोरी भी शामिल है। इसको कम कर 15 प्रतिशत तक लाया जाए तभी स्थिति सुखद कही जाएगी। पुराने तारों और अन्य उपकरणों को बदल कर लोड के अनुरूप नए उपकरण लगाने से स्थानीय फाल्ट कम होंगे। योगी सरकार के गठन के बाद ऊर्जा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि जिस फीडर में लाइन लास कम होगा व बिल की शत प्रतिशत वसूली होगी वहां और अधिक बिजली दी जाएगी। पावर कारपोरेशन की मशीनरी को उत्साह से कार्य करने की जरूरत है, उपभोक्ताओं को भी स्वेच्छा से बिल अदायगी की आदत डालनी होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दिल्ली सरकार और प्रशासन के बीच टकराव टालने के लिए सीएम केजरीवाल को मुख्य सचिव से माफी मांगनी चाहिए?

आज का सवाल

क्या पचास करोड़ रुपये से अधिक के फंसे कर्जों की जांच से बैंकों के एनपीए की समस्या का कुछ समाधान निकलेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आसानी से नहीं सुधरेगा पाकिस्तान

विवेक काटजू

एफएटीएफ की बैठक में अमेरिकी रुख दर्शाता है कि पाकिस्तानी जनरलों को कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन क्या वे आतंकी समूहों को जड़ से खत्म करेंगे?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 'ग्रे' सूची में डालने की तैयारी कर ली है। यह उन देशों की ऐसी निगरानी सूची होती है जो आतंकी समूहों तक वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति को सक्षम रूप से नहीं रोक पाते। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, फिर भी एक आर्थिक कदम के रूप में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन मुश्किल और महंगे हो जाएंगे। विशेषकर पाकिस्तानी बैंकों में वैश्विक भरोसे में कमी आएगी। साथ ही ऐसे लेनदेन गहन निगरानी के दायरे में भी आ जाएंगे और पाकिस्तान के सामान्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन में देरी भी होगी। पाकिस्तान किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहेगा खासतौर से तब जब वह एफएटीएफ के निशाने पर आकर पहले भी इसका खामियाजा भुगत चुका है जब 2012 से 2015 के बीच उसे 'ग्रे' सूची में डाल दिया गया था। एफएटीएफ के निर्णय के जहां पाकिस्तान के लिए गंभीर आर्थिक निहितार्थ हैं वहीं इसके राजनीतिक एवं कूटनीतिक हालात भी उसके लिए और भी ज्यादा चिंता का सबब हैं। पेरिस में हुई हालिया बैठक में पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की तैयारी से पहले शुरुआती चर्चा में चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने पाक को निगरानी सूची में डालने के प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध को लेकर उनकी दलील यही थी कि पाकिस्तान को तीन महीनों की मोहलत दी जाए ताकि वह बैंकिंग क्षेत्र में जरूरी कदम उठाकर एफएटीएफ को संतुष्ट कर सके और यदि इसके बाद भी वह इस पैमाने पर खरा न उतरे तो उसे निगरानी सूची में डाला जाए। पाकिस्तान ने सोचा कि अपने मित्रों की मदद से उसने यह मोहलत हासिल कर ली है। यहां तक कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस मोर्चे पर अपने मुल्क की कामयाबी को लेकर ट्वीट भी कर दिया। वहीं अमेरिका पाकिस्तान को ऐसी किसी भी रियायत के लिए तैयार नहीं था। उसने सऊदी अरब को मजबूर किया कि वह पाकिस्तान को घेरने में उसकी मदद करे। उसने पाकिस्तान को लेकर एक और बैठक बुलाने की मांग की। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का समर्थन किया। वहीं चीन भी दीवार पर लिखी इबारत को भांप चुका था।

पाकिस्तानी मीडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को सूचित किया कि वह अगले दौर में चर्चा और मतदान से किनारा करेगा। अब केवल तुर्की पाकिस्तान के साथ रह गया। हालिया दौर में अमेरिका के साथ तुर्की के रिश्ते भी कुछ तल्ख हुए हैं। आखिरकार एफएटीएफ ने पाकिस्तान को तब तक के लिए निगरानी सूची में डालने का फैसला किया जब तक कि वह वित्तीय संस्थानों को पूरी तरह चाकचौबंद कर यह सुनिश्चित नहीं करता कि वे किसी भी तरह आतंकियों द्वारा इस्तेमाल होने की आशंकाओं को खारिज करेंगे। चूंकि इस प्रक्रिया में तीन महीने का समय लगेगा तो अंतिम फैसला एफएटीएफ की अगली बैठक में ही लिया जाएगा। यदि पाकिस्तान कोई स्वीकार्य योजना पेश नहीं करता तो एफएटीएफ उसे काली सूची में भी डाल सकता है। फिलहाल केवल ईरान और उत्तरी कोरिया ही काली सूची में शामिल हैं। सुरक्षा और विदेश नीति को संचालित करने वाली पाकिस्तानी सेना राहत के लिए हमेशा अपने सदाबहार दोस्त चीन पर भरोसा करती है। वह यह मानकर चल रही थी कि एफएटीएफ जैसी मुश्किल से चीन उसे बाहर निकाल लेगा, लेकिन इस बार चीन ने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह अमेरिका से पंगा मोल नहीं लेगा, क्योंकि शायद उसे कामयाबी भी न मिले। इसका अर्थ यह नहीं कि चीन सभी मामलों में पाकिस्तान को उसके हाल पर यूं ही छोड़ देगा।

अवधेश राजपूत

भारत को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में डालने और भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों यानी एनएसजी में जगह दिलाने में वह किसी तरह की मदद करेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान इससे जरूर सबक लेगा कि अगर अमेरिका उस पर दबाव बनाने को लेकर अपने रुख पर अड़ जाए तो फिर उसके मित्र भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तोइबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाएगा?

इस बारे में अभी कुछ कहना कठिन है, लेकिन एफएटीएफ की कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली अखबार डॉन के संपादकीय पर गौर करना खासा उपयोगी होगा जिसका मजमून कुछ इस तरह है, 'अब यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी उस नीति के चलते दुनिया भर में अलग-थलग पड़ता जा रहा है जिसके तहत यह कहा जाता है कि वह अपनी आधिकारिक नीति में आतंकी कहे जाने वाले समूहों को प्रश्रय देता है।' भारत भी दो दशकों से यही कहता आ रहा है। अब पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने भी यह स्वीकार किया है। क्या पाकिस्तानी फौज के जनरल इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिकी कार्रवाई पाकिस्तानी फौज को जरूर चिंता में डालेगी जो अभी तक यही माने बैठी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम कड़ी चेतावनियों के बावजूद उनकी अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया नीति उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से ज्यादा अलग नहीं होगी। पाकिस्तानी सेना यह भी सोचकर चल रही थी कि ट्रंप इतना दबाव नहीं बढ़ाएंगे कि उसे दूसरे देशों में आतंक फैलाने वाले आतंकी समूहों पर लगाम लगानी पड़े।

एफएटीएफ बैठक में अमेरिकी प्रस्ताव दर्शाता है कि पाकिस्तानी जनरलों को कुछ न कुछ दिखावटी कदम जरूर उठाने होंगे, लेकिन क्या वे इन समूहों को जड़ से खत्म करने की सोचेंगे? जब तक इस मामले में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिलते तब तक इस सवाल का जवाब नहीं ही होगा। इसकी तमाम वजहें हैं। पाकिस्तान की विदेश और रक्षा नीतियां भारत केंद्रित हैं। पाकिस्तान भारत को स्थाई खतरे और दुश्मन के तौर पर देखता है। भारत से तथाकथित खतरे की काट के लिए उसने ऐसा सुरक्षा सिद्धांत अपना लिया है जिसके एक सिरे पर परमाणु बम है तो दूसरे पर आतंकी समूह। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसके सुरक्षा बल भारत से कमजोर हैं। आतंकी समूहों का इस्तेमाल उसके सुरक्षा सिद्धांत का अहम पहलू है। उनके जरिये पाकिस्तान भारत को रक्षात्मक बनाकर कश्मीर के मामले में दखल चाहता है। पाकिस्तानी सेना विकल्पहीनता की स्थिति में ही आतंकी समूहों को तिलांजलि देगी। एफएटीएफ की कार्रवाई दबाव बढ़ाएगी, लेकिन यह सेना में बदलाव के लिहाज से नाकाफी होगा। आतंकी समूहों ने पाकिस्तानी समाज-सियासत में भी गहरी जड़ें जमा ली हैं। सबसे प्रभावशाली प्रांत पंजाब में उन्हें व्यापक समर्थन हासिल है। इन समूहों पर कड़ी कार्रवाई से असंतोष और यहां तक की हिंसक गतिविधियां भी फैल सकती हैं। सेना के लोगों के लिए भी इन समूहों के नेता नायक वाला दर्जा रखते हैं। ध्यान रहे कि पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रहे जनरल परवेज मुशर्रफ आतंकी हाफिज सईद को हीरो बता चुके हैं।

(लेखक विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव और पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

क्रिकेट बोर्ड में सुधार का इंतजार

शिवेंद्र कुमार सिंह

क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा नहीं तय करनी चाहिए?

भारत में इन दिनों क्रिकेट का संचालन सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी सीओए यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स करती है। इस कमेटी के पास तमाम अधिकार हैं। यह कमेटी इस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी कि इसके जरिये क्रिकेट में पारदर्शिता लाई जाएगी और क्रिकेट के खेल में अंदर तक घुस चुकी खराब राजनीति का अंत होगा, घाघ क्रिकेट प्रशासकों की मनमानी पर रोक लगेगी तथा खेल को स्पॉट फिक्सिंग और ऐसी ही कुछ और बदनामियों से भी बचाया जाएगा। अभी तक इन मुद्दों पर इस कमेटी को कितनी कामयाबी मिली, यह बहस का ही मुद्दा बना हुआ है। इसी के साथ बहस का मुद्दा यह भी है कि क्या इस कमेटी को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा नहीं तय करनी चाहिए?

आखिर अन्य अनेक मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट समयसीमा तय करता रहता है। आज इस मुद्दे को उठाने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कमेटी या फिर कमेटी और बीसीसीआइ के बीच की खींचतान के कारण ही दक्षिण अफ्रीका से ऐतिहासिक सीरीज जीतकर लौटी भारतीय टीम की अनदेखी सी हुई है। जरा सोचकर देखिए कि विराट कोहली की अगुआई में भारतीय टीम ने दुनिया की नंबर एक वनडे टीम को 5-1 से हराया, लेकिन टीम के स्वदेश लौटने पर कोई स्वागत-सत्कार नहीं। इस सीरीज के सभी मैचों में हार का अंतर इतना बड़ा था कि क्रिकेट फैंस ताज्जुब कर रहे थे कि मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे हैं या भारत में? वनडे सीरिज के बाद टी-20 सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम की हालत कुछ ऐसी ही हुई। भारत ने टी-20 सीरीज 2-1 से जीती।

बीते 25 सालों में यह पहला मौका है जब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में कोई वनडे सीरीज जीती है। टी-20 सीरीज की जीत भी एक इतिहास ही है। वनडे सीरीज की जीत के साथ ही भारत ने वनडे रैंकिंग्स में दक्षिण अफ्रीका से नंबर एक का ताज भी छीन लिया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी बीसीसीआइ या फिर उसे चलाने वाली सीओए ने खिलाड़ियों के सम्मान में न तो किसी इनाम का एलान किया न ही खिलाड़ियों का वैसा स्वागत हुआ जैसा अपेक्षित था। यह कितना अजीब है कि दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में वनडे और टी-20 सीरीज में बुरी तरह धोने वाले खिलाड़ियों में से शिखर धवन, एमएस धौनी, भुवनेश्वर कुमार आदि को एयरपोर्ट से सन्नाटे में निकलते विजुअल्स टीवी चैनलों पर चल रहे थे। इस सिलसिले में दो किस्सों का जिक्र जरूरी है। 2004 में भारतीय टीम करीब 14 साल बाद पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर गई थी। सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे। उस सीरीज को दोनों देशों के बदलते रिश्तों के तौर पर बहाल किया गया था। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने वहां वनडे और टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। उस सीरीज को जीतने के बाद जब भारतीय टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां कई घंटे तक पैर रखने की जगह नहीं थी। इससे पहले का भी एक इतिहास है। साल था 1971। अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से जीतकर लौटी थी। तब एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग अपने चैंपियंस के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे।

क्रिकेट फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को बेताब थे। खुली कारों में खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से बाहर लाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि तब बीसीसीआइ के पास न तो इतने संसाधन थे और न ही इतना पैसा। कुछ था तो वह था जीत को सलाम करने का जज्बा। अब वही बीसीसीआइ जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है अपने क्रिकेट सितारों और उनकी कामयाबी की मुनादी करना भूल गया। अगर इसके पीछे तर्क यह दिया जाए कि 2011 में विश्व कप जीतने के बाद खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ था तो बहस इस दिशा में भी मुड़ेगी कि क्या विश्व कप में मिली जीत के अलावा बाकी की जीतों का कोई महत्व नहीं है? अगर महत्व नहीं है तो फिर दो देशों की सीरीज खेलने का औचित्य क्या है?

पिछले कुछ सालों से यह रवायत थी कि किसी भी सीरीज में जीतने के बाद बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से टीम को बधाई देने वाले ईमेल मीडिया को भेजे जाते थे और बड़ी जीत के बाद खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का एलान भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त उनका स्वागत होता था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने-अपने शहर में इस तरह लौटे कि यह लगा ही नहीं कि वे कोई इतिहास रचकर आ रहे हों। इस बात का मलाल खिलाड़ियों के मन में जरूर होगा। हाल में एक और वाकया हुआ, जिसका जिक्र यहां करना जरूरी है। अंडर-19 विश्व कप जीतकर लौटी टीम के सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों और कोच राहुल द्रविड़ की इनामी राशि में फर्क था। राहुल ने अपनी इनामी राशि कटवा कर उसे बाकी सदस्यों में बराबरी से बंटवा दिया। जिन खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की वजह से बीसीसीआइ की कमाई होती है उन्हें नजरअंदाज करना खुद को कटघरे में खड़ा करने जैसा ही है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि बीसीसीआइ में तमाम विसंगतियां आ गई थीं और उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी भी साफ महसूस की जा रही थी। उसके ज्यादातर फैसले बंद कमरों में होते थे। क्रिकेट के खेल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो खेल की गरिमा के खिलाफ था। सीओए का गठन क्रिकेट को इन्हीं सबसे बचाने के लिए किया गया था। अफसोस इस बात का है कि लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी स्थितियां ठीक होती नहीं दिख रही हैं। कई लोग अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं। अदालत का डर तो है, लेकिन उससे बच निकलने के रास्ते खोजने की कोशिश जारी है। शायद इसी कवायद के चलते बीसीसीआइ के संचालक यह भूल रहे हैं कि विराट कोहली, धौनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार जैसे सितारों के प्रदर्शन की बदौलत ही जीत है, जीत की बदौलत फैंस और फैंस की बदौलत बाजार और बाजार की बदौलत पैसा है। इनमें से एक भी कड़ी का टूटना खेल की लोकप्रियता के लिए अच्छा नहीं है।

(लेखक खेल पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शरीर

शरीर साधन भी है तो साध्य भी है, जीवन से जुड़ी इससे बड़ी कोई हकीकत हो नहीं सकती और इसलिए आज के भौतिकतावादी दौर में इसे ठीक से और बार-बार समझने की जरूरत है। यह बात सरसरी तौर पर तो सामान्य लगती है, लेकिन गहराई में जाने पर इसकी महत्ता का ज्ञान होता है। अपने इर्द-गिर्द जो भी भौतिक संसार हम देखते हैं उसकी जड़ में जाएं तो पाएंगे कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन शरीर के लिए ही है। मकान, दुकान, कारखाने, इत्यादि वस्तुएं और गतिविधियां सब कुछ इस शरीर के लिए आवश्यकतानुसार बनाई गई हैं। पूरा का पूरा सांसारिक तानाबाना इस शरीर रूपी ध्येय के लिए खड़ा किया गया है। साथ ही जब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं तो पाते हैं कि इस ताने-बाने को खड़ा भी इस शरीर द्वारा ही किया गया है। अर्थात इस जगत में बनी हर चीज 'इंसान ने इंसान के लिए' बनाई है और जिसमें इंसान का बनना भी शामिल है। यहां हम विषय को व्यावहारिकता से समझने के लिए इंसानी अस्तित्व के ईश्वरी और आध्यात्मिक पहलू को फिलहाल अलग रखकर विचार कर रहे हैं।

सामान्य सी प्रतीत होने वाली बात भी चिंताजनक तब हो जाती है जब इंसान साधनों का संग्रहकर्ता मात्र बनकर रह जाता है। वह भूल जाता है कि जो भी साधन-संसाधन वह इकट्ठा कर रहा हैं वे सब उसके लिए भी हैं और उसे कुछ समय इनके इस्तेमाल के लिए भी निकालना चाहिए। यहां कभी-कभी हम साधनों को साध्य पर हावी हुआ पाते हैं और इंसानी जीवन को ही ग्रहण लगाने वाले कार्य करने लग जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि इंसान ने यह समस्त भौतिक जगत जीवन की आवश्यकता और सुगमता के लिए सृजित किया है। जब इंसान का अस्तित्व ही शरीर से परे है ही नहीं तो फिर संग्रहकारी प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं के चलते इस शरीर को ही दांव पर लगाने की मूर्खता क्यों की जाए। यह सही है कि इंसान को केवल और केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी प्रवृत्त रहना चाहिए, लेकिन किसी हद तक ही। ऐसे में शरीर और जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

डॉ. महेश भारद्वाज

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

महिला सशक्तीकरण वास्तविक है

मृणाल पांडे का लेख महिला सशक्तीकरण की स्याह तस्वीर (28 फरवरी) वर्तमान सरकार के प्रति उनके पूर्वाग्रह-पूर्ण रुख को ही दर्शाता है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या भारत के इतिहास में ऐसा प्रथम बार नहीं हुआ है कि तमाम महिला कर्मचारियों (सरकारी-गैरसरकारी दोनों) को 6 मास का मातृत्व अवकाश मंजूर हुआ। अब से पूर्व मात्र 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। गर्भवती महिला कर्मचारी प्रसव से एक दिन पूर्व तक कष्ट सहन करते हुए कार्यस्थल पर काम में जुटी रहने को विवश रहती थी। मुस्लिम महिलाओं, जिनकी संख्या 10 करोड़ होगी, के सर से तीन तलाक की लटकती तलवार हटाना क्या सशक्तीकरण का मूलभूत प्रयास नहीं है? अब आगे हलाला एवं बहुपत्नी प्रथा समाप्त करने का नंबर आ रहा है। उज्ज्वला योजना से 5 करोड़ निर्धन महिलाओं को चूल्हे के धुंए से मुक्ति दिलाना कितना बड़ा कदम है। मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने हेतु 14 योजनाएं/कार्यक्रम चलाएं हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, श्रमजीवी महिला हॉस्टल, एसटीईपी (स्टैप) यानी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, महिला ई-हाट, महिला शक्ति केंद्र, नारी शक्ति और स्त्री शक्ति पुरस्कार आदि आसानी से गिनाए जा सकते हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु बैंक कम ब्याज पर ऋण देते हैं। सेना में युद्धक भूमिका में पहली बार उन्हें आगे लाया गया है। लेखिका को पूर्वाग्रह-दुराग्रह का चश्मा हटाकर वास्तविकता को देखना चाहिए।

अजय मित्तल, मेरठ

श्रीदेवी का यूं चले जाना

अभिनेत्री श्रीदेवी के आकस्मिक निधन से उनके करोड़ों चाहने वालों को सदमा लगा है। करोड़ो को रुलाकर वह हमेशा के लिए अलविदा हो गईं। दुबई की वो मनहूस रात श्रीदेवी की आखरी रात साबित हुई। इसके पहले कई ख्याति प्राप्त कलाकारों की असामयिक मौत हो चुकी है, लेकिन बाथटब में इस तरह मौत हो जाना हतप्रभ करने वाला है।

kantilalmandot@gmail.com

स्वस्थ खान-पान

इधर बच्चों में जंकफूड का प्रचलन ज्यादा बढ़ा है। ये उत्पाद बच्चों के शारीरिक विकास व मानसिक विकास पर असर डालते हैं। इससे दांतों की बीमारी, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे उत्पादों के ज्यादा चलन से भारतीय संस्कृति का परम्परागत और देशी खाना पीछे छूट गया, क्योंकि जंकफूड की लत के बाद घर का खाना भी अच्छा नही लगता है। कई रिपोर्ट से सामने आया है कि जंक फूड उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाली खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए सही नही है, लेकिन ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। जंकफूड का बाजार बहुत बड़ा है। इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल स्तर पर बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि स्वास्थ्यवर्धक खान-पान और स्वस्थ आदतों को अपनाया जाए।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

नियुक्ति प्रक्रिया

डा. भरत झुनझुनवाला का लेख, बेलगाम हैं भ्रष्ट नोकरशाही, को पढ़ा। उन्होंने भारत के पूर्व विद्वान् दार्शनिको के द्वारा शासन में चलाए जाने वाले नियम का जिक्र करते हुए चाणक्य के अर्थशास्त्र के नियम बताए। मगर यह नियम का लाभ तभी मिल सकता है, जब नियुक्ति में भी चाणक्य के ही नियम अपनाए जाएं अन्यथा सब कुछ लाभहीन होगा। सरकार की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया ही दोष पूर्ण है। इसमें केवल रट्टू तोते ही चुने जा सकते हैं।

सुमनवीर सिंह पौरुष, पलवल

मन का भी एक रंग

रंगों की रंगत का अहसास होली के रंगों को देखकर ही होता है। ये रंग न सिर्फ अपनी इन्द्रधनुषी छटा से परिवेश को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि मन, मस्तिष्क, भाव, स्वभाव पर भी असर डालते हैं। पसंदीदा रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। हर रंग कुछ कहता है। लाल रंग शक्ति, उत्साह तो नीला रंग परस्पर विश्वास और पीला रंग रचनात्मकता तो हरा रंग शांति, प्यार, एकता में वृद्धि करता है। बैंगनी रंग सांसारिक संपन्नता को दर्शाता है। प्रकृति की सुन्दरता लिए ये रंग कभी भी आत्मा को आनन्दविभोर किए बिना नहीं रहते। ऐसे में रंग के अहसास को सिर्फ होली पर महसूस करना उनके साथ नाइन्साफी होगी। आज होली के हुड़दंग से बचने के लिए भले ही कुछ लोगों ने रंग खेलने से दूरी बना ली हो, लेकिन रंग के अहसास से वे भी परिचित हैं। हर व्यक्ति जिन्दगी में अपने ढंग से रंग भरता है। रंगों के बिना जीवन प्राण बिन शरीर की तरह है। उम्र का हर पड़ाव रंगों को अपने ढंग से अनुभूत करता है। बच्चे रंगों की सहायता से ही वस्तुओं को पहचानते हैं। युवा रंगों के माध्यम से ही संसार का सृजन करते हैं। वृद्धों की पथराई आंखें रंगों के माध्यम से ही वस्तुओं के नाम प्राप्त करती हैं। जिन्दगी खुशी और गम का संयोग मात्र है। मनुष्य के अहसासों, जिन्दगी के उतार-चढ़ाव व मानवीय मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए भी रंगों का सहारा लिया जाता है। लाल, हरे, पीले, नीले, बैंगनी, नारंगी रंगों के अलावा भी एक रंग होता है जिसे मनुष्य के मन का रंग कहते हैं। यह इन्सानियत का, मानवीय मनोभावों का, आपसी प्रेम और भाईचारे का रंग है। इसके बिना सभी रंग अधूरे हैं। दुनिया के सारे रंग एक अंतराल के बाद छूट जाते हैं। एक स्थायी, सदा कायम रहने वाला रंग मन का रंग ही है।

joshi.devendra85@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

कांचीपुरम मठ के शंकराचार्य जगदगुरु पूज्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के शरीर छोड़ देने से मुझे व्यक्तिगत आघात लगा है। वह हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे।

उमा भारती@umasribharti

लगता है कि ओडिशा अभी भी नवीन पटनायक का ही है। भाजपा और कांग्रेस वहां दूसरे पायदान की लड़ाई में हैं। वहीं एमपी शिव के राज से ऊब चुका है, यह संदेश दिख रहा है।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

टीवी न्यूज ने भारत में पत्रकारिता को नष्ट कर दिया। टीवी न्यूज को खुद को ठीक करना होगा और फिर से अच्छी टीवी पत्रकारिता की ओर लौटना होगा।

चित्रा सुब्रमण्यम@chitraSD

कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी का वक्त ठीक नहीं। उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता तो लोग सरकार की सराहना करते। अभी वे इसे नीरव मोदी से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर देखेंगे। चुनाव से पहले शायद वाड्रा की बारी आए।

सुमंत रमन@sumanthraman

सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के साथ सबसे पहले कौन अस्पताल में भर्ती होने जा रहा है- कार्ति या पी चिदंबरम? पहले जेल जाने से बचना है फिर विक्टिम कार्ड खेलना है।

मोहन सिन्हा@Mohansinha

जनपथ

होली मस्त जलाइए जले साथ में बैर,
जले चांदनी रात में दुनिया की अंधेर।
दुनिया की अंधेर उड़े चहुँ ओर अबीरा,
गाएं बाल-बुजुर्ग पोतकर रंग कबीरा।
गुंझिया-पापड़ खाय कीजिए खूब ठिठोली,
बंधु मुबारक होय आपको प्यारी होली।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 226